



कार्यालय
अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा-गढवाल

E-mail id :-
eepwddugadda@gmail.com
eepwddugadda@rediffmail.com
Phone & Fax No :-01382-251221

पत्रांक ...3.7.66/19110

दिनांक ..24/8/22

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडॉन वन प्रभाग
कोटद्वार गढवाल

विषय :- जनपद पौड़ी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा, दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा-तच्छाली-स्यालिंगा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.8675 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (On line no. FP/UK/ROAD/ 152108/ 2022)

संदर्भ :- कार्यालय-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/49/2022/एफ0 सी0/543 दिनांक 15/07/2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वांछित 22 बिन्दुओं की सूचना का निराकरण निम्नानुसार है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वांछित सूचनायें	सूचना का बिन्दुवार निराकरण
1.The total cost of the project is 408.5 lacks. However , the administrative and financial approval is provided only 61.00 lacks. The State Government is requested to submit the proposal with fresh administrative and financial approval.	प्रस्तावित मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2550/ 111(2)/16- 19 (प्रा0आ0) /2016 दिनांक 04 अक्टूबर 2016 के द्वारा रू0 60.80लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। 408.5 लाख नहीं है।(प्रमाणित छाया प्रति 5 प्रतिशत में संलग्न है।)
2.The State Government is requested to confirm from the user Agency if the civil construction measures provided in the Geologist recommendations are incorporated in, the estimate. A copy of the estimate is also required to be provided.	नियमानुसार मोटर मार्ग के निर्माण का विस्तृत आगणन वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त तैयार किया जाना है।
3-Details of the non-forest land are not provided online at para A(I)(ix), para B in Part I.State Government is requested to provided the requisite information at para A(1)(ix),para B in part -I and wherever required.	Online para A(1)(ix),para B in part -I में एवं सभी जगह जहां आवश्यकता है, गैर वन भूमि (निजी नाप भूमि)2-6325 हे0 को दर्ज कर दिया गया है।
4-Village wise break-up of the proposed area is not provided at B 2.3 in Part-I . Village wise break-up of area is required to be provide at B 2.3 in Part-I .	B 2.3 in Part-I में ग्रामवार भूमि का प्रकार और क्षेत्रफल दर्शा दिया गया है।
5-Component wise break-up viz, road, muck dumping area, etc. Of the prorosed project area is not provided at B 2.4. The State Government is requested to provide the necessary information.	B 2.4 in Part-I में Component wise break-up मोटर मार्ग व मक डिस्पोजल का क्षेत्रफल अलग-अलग दर्ज कर दिया गया है।

6-Incorrect KML. file is uploaded in online Para-C (ii)(b). As per this KML file the proposed area is located in some part of Uttar Pradesh State Government is requested to upload the correct KML file.	प्रस्तावित परियोजना के संरेखण की सही के0एम0एल0 फाईल Para-C (ii)(b)में आनलाइन अपलोड कर दी गई है।
7-At para D in Part-I, Site inspection report is uploaded in place of justification for loating the project in forest land and details of alternatives examined. State Government is requested to upload the correct information.	पार्ट-। के पैरा डी-। में परियोजना के औचित्य का प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया है। पूर्व में गलत अपलोड की गयी स्थल निरीक्षण आख्या हटा दी गयी है।
8-Detail of alternatives examined is not submitted at para D (ii) a and the reason provided for the same is also not acceptable. State Government is requested to	पार्ट-। के पैरा डी-।। में वैकल्पिक समरेखन जिस पर विचार किया गया था मैप में दर्शा कर अपलोड कर दिया गया है।
9-Proceedings of Village Level Committee (VLC) meetings of the villages Pulinda and Katal under under FRA are not uploaded. State government is requested to upload the same at para K. However , the same way be uploaded prior to the stage -II approval .	ग्राम पुलिण्डा एवं काटल की ग्राम समितियों की बैठक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र में संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।(प्रमाणित छाया प्रति 5 प्रतिियों में संलग्न है।)
10-KML file of area proposed for diversion is uploaded in place of KML file for CA area at para L in part I as well as at para 13 in part II. State Government is requested to upload the correct KML file.	पार्ट-। के पैरा एल-सी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी गयी है।
11-Total five villagers are mentionrd to be benefited from the road but location of only three villagers is marked on the KML file. State Government is requested to mark the location of all the five villages that are likely to be benefitted from the proposed road.	पार्ट-1 के पैरा सी में मोटर मार्ग की सही के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर दी गयी है। ग्राम पुलिण्डा पूर्व से ही मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ है लेकिन इस नये मार्ग बनने से ग्राम पुलिण्डा के सामाजिक / व्यवसायिक हित अन्य 4 ग्रामों से होने के कारण ग्राम पुलिण्डा भी लाभान्वित ग्रामों में सम्मिलित है। इस प्रकार मोटर मार्ग के संरेखन की के0एम0एल0 में ग्राम पुलिण्डा एवं ग्राम काटल को दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है।
12- Muck dumping sites are not marked in the KML file .State Government is requested to mark the location of the muck dumping sites on the KML file of the proposed diversion area.	मलवा निस्तारण स्थल के0एम0एल0 फाईल में पीले बिन्दुओं से एवं मानचित्र में काले बिन्दुओं से निर्देशांक की सूची सहित दर्शाया गया है जो पार्ट-। के पैरा-सी में अपलोड किया गया है।
13-CA site suitability certificate uploaded at para L (iv) (h) is not authenticated by DFO. Authenticated CA site suitability certificate is required to be submitted	para L (iv) (h) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा प्रमाणित कर अपलोड किया गया है, जो पूर्व ही पत्रावली के पृष्ठ संख्या-80 में संलग्न है।
14-The details filled in the part II, at para 8(i) and 8(ii) regarding the presence of the wildlife in the proposed area are contradictory . Same may be revised and submitted accordingly by the DCF.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
15-As per the information provided in the part II of the proposal, the proposal alignment of the road falls in the shivali Elephant reserve and the Rajaji Tiger Reserve , hence the details of the Wildlife Clearance taken from the SBWL and NBWL is required to be provided along with the mitigation measures to prevent the adverse effect on the wildlife.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
16-It has been mentioned at para 8 that elephant proof solar fencing is proposed to control human-wildlife conflict in the area .State Government is requested to submit the seif-explanatory plan , if any, prepared in this regard.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

17-CA scheme uploaded online is not legible , State Government is requested to upload a clear copy of the CA scheme.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
18-The girth wise and species wise enumeration of the trees provided at para 4 in part II do not match with the details provided in format 15.4. State Government is requested to upload the correct species wise and girth wise enumeration of trees.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
19-In the land schedule the width of the proposed road is mentioned as 9 meters. State Government is requested to restrict the same up to 7 meters only and submit the revised land schedule accordingly.	मुख्य अभियन्ता स्तर-। लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक 1715/01 व0भू0-सामान्य-10 दिनांक 2.12.2010 के अनुसार सड़क निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 9 मी0 चौड़ाई में ली गयी है एवं मार्ग में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गिनती 7 (ROW) मीटर चौड़ाई में की गयी है। आदेश की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।
20-In view of the point No.19 the tree enumeration list is also required to be revised considering the road width as 7 meters only.	बिन्दु संख्या-19 के अनुसार।
21-On the perusal of the bar chart uploaded in part II, it is noticed that the Van panchayat land and the Non-forest land are shown in the same colour. State Government is requested to do the needful in tis regard.	बार चार्ट में सिविल भूमि को पीले रंग से वन पंचायत भूमि को बैंगनी रंग से व आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से एवं निजी नाप भूमि को भूरे रंग से सही नाप के अनुसार दर्शाकर अपलोड कर दिया गया है।(प्रमाणित छाया प्रति 5 प्रतियों में संलग्न है।)
22-Blank NPV sheet is found uploaded in part I. State Government is requested to submit/ upload the correct copy of NPV calculation sheet as per the new duly authenticated by the competent authority.	इस बिन्दु का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि परियोजना के निर्माण हेतु कुल न्यूनतम 1.8675 हे0 आपेक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सूचना अग्रसारित करने का कष्ट करें।

Hudson

(डी0पी0 सिंह)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

पत्रांक 3766 / 19

- प्रतिलिपि:-1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2- वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3- सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता नि0ख0, लो0नि0वि0 दुगड्डा गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

संख्या 2550/III(2)/16-19(या0आ0)/2016

प्रेषक, अरविन्द सिंह ह्यूको, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

लोक निर्माण अनुभाग-2
विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत 02 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय, उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता को का 0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 02 कार्यों के प्रथम चरण के आगमन, जिनकी लम्बाई 5.20 किमी लागत ₹ 61.00 लाख है; पर विभागीय टीओपीओ द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 61.00 लाख (एक सठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 (दो बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय दिनांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका सप्तायोजन विस्तृत आगमन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगमन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वोरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2008 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगमन में एनओपीओवी, भूमि अधिग्रहण, म्यूटिलिटी सिफिटींग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5064 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों आयोजनागत-800 अन्य व्यय-05 सड़क/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00

Photocopy attached AJ

आमा प्रति सत्यापित

long

आमा प्रति सत्यापित
खण्ड लोक निर्माण विभाग (गढ़वाल)

Photocopy attached

Photocopy attached

-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राक्खानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अभिराशी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे उाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-815(A)/XXVII(2)/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक : यथोपरि।

सुबदीय

(अरविन्द सिंह हर्षाकी)
प्रभारी सचिव

संख्या- 550 / 11(2)/16-19(प्रोआ0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल सण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमौली/देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, से0का0, लौन्कि0, पौड़ी/देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अभिराशी अभियन्ता, उत्तराखण्ड।

हस्ताक्षरित स्थापित

for up

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
हल्द्वारा (गढ़वाल)

आज्ञा से,

(सोएसो बागती)
उप सचिव

Photocopy
attested
AJ

Photo copy attested
Jude

Photo copy attested

संख्या- 2550/111(2)/15-19(प्रोजेक्ट)/2016 दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक।
(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	वित्तीय टीएणसीए द्वारा अनुमोदित लागत	शालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत अन्वीवाला गुरुद्वारा (रिंग रोड) विध्य विहार नजदीक राजीव नगर देहरादून तक सड़क निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.20	0.20	0.10
2	महो मुख्यामत्री जी घोषणा संख्या-1106/2015 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगडडा ब्लॉक के पुलिण्डा तहसीली स्वाबिगा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	60.80	0.10
कुल :-		5.20	61.00	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

[Signature]
Asst. Commr.

होमिनी सत्यापित

Photocopy attested
Aj

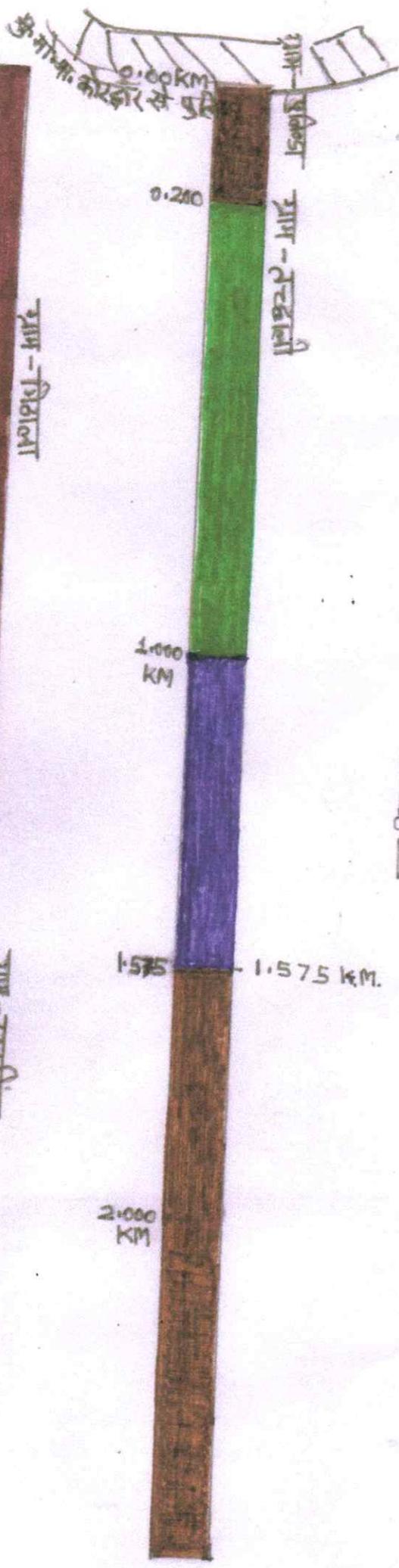
[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० मि वि०
(गढ़वाल)

Photo copy attested
[Signature]

सूचना सं. 21

SCALE - 1 CM = 100 Mtr.

बार = यदि



ग्राम - तुलिका

3.000 KM.

ग्राम - तुलिका

4.000 KM

4.300

4.600 KM

5.000 KM

ग्राम - तुलिका

एम्प्लोई एम्प्लोई

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. सि. वि. ७
दाहडा (राजवाल्)

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	रंग
1-	आरक्षित भूमि	हरिया
2-	वन पंचायत भूमि	नीला
3-	नाप भूमि	लाल
4-	खाली वन भूमि - शरण	पीला

Additional Assistant Engineer
C D PWD Durgada

अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. सि. वि. ७
दाहडा (राजवाल्)

अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. सि. वि. ७
दाहडा

प्रशासक वनीकरण
नैसर्गिक वन प्रभाग
कोटद्वार (राजवाल्)

क्रमांक- 576
दिनांक-
कम संख्या-
विद्युत संदम-

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पत्रांक- 1715 / 01 व 0 भू-सामान्य-10
सेवा में,

दिनांक- 02/12/10



मुख्य अभियन्ता, (गो/कु) क्षेत्र,
लोक निर्माण विभाग,
पौड़ी/अल्मोड़ा।

विषय:- स्वीकृत मोटर मार्गों के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मीटर चौड़ाई में प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखण्ड द्वारा नोडल अधिकारी वन पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों का उल्लेख करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव 07 मी0 चौड़ाई में प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है; साथ ही उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव इससे अधिक 12 मी0 एवं 09 मी0 चौड़ाई के प्रेषित किये जाने पर काफी अधिक वृक्षों के पातन के साथ-साथ प्रस्ताव प्रेषित करने में ही खींचतान होने से प्रस्ताव स्वीकृत होने में काफी विलम्ब होता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है, कि किसी भी मार्ग निर्माण में वन भूमि प्रस्ताव हेतु मार्ग की चौड़ाई (Row) 9 मी0 ली जाय व मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की गिनती 7 मी0 चौड़ाई में की जायेगी। उपरोक्तानुसार अधीनस्थों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

प्रतिलिपि:- श्री खड़क सिंह बोहरा जी, मा0 विधायक, नैनीताल विधान सभा क्षेत्र, नैनीताल को उनके पत्र सं0 3553 दिनांक 16.11.2010 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, 1154 वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1

6/12/10

6.12.10

सं- 4486/57 मा-1/10 सं- 6-12-10

4486
6-12-2010

पौड़ी/पौड़ी विभाग/लोक निर्माण विभाग/देहरादून/वृक्षों को हटाने के लिए प्रेषित

दादा जगेंद्र लाल

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०
देहरादून (गडवाल)

12वां वृत्त लो०नि०वि०
पौड़ी गडवाल

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि०मी०) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम सभा का नाम- काटल ग्राम -काटल
तहसील-कोटद्वार जिला- पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

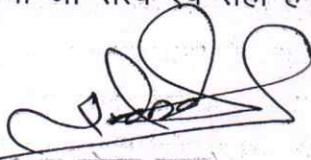
उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.080 हे० सिविल वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि 0.7875 हे०) 1.8675 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा - काटल के ग्राम - काटल द्वारा दिनांक 13-8-2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- पुलिण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग दुगड़डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित


(इन्द्र मोहन राणा)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि० ख० दुगड़डा
पौड़ी गढ़वाल



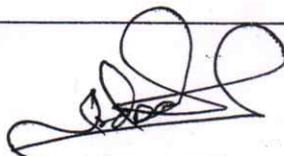

D:\ANIL MYNEW VAN BHUMI PRARUP\TCCHALI-SYALINGA.docx (Page-56)

सहायक अभियन्ता
वि० ख० दुगड़डा लो० नि वि०
(पौड़ी गढ़वाल)

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0
-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के
पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)
ग्राम -काटल दिनांक 13-08-2022

क्रम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मंगल सिंह	मंगल सिंह
2-	बनयन सिंह	बनयन सिंह
3-	सावन सिंह	सावन सिंह
4-	शेखन सिंह	शेखन सिंह
5-	सावन सिंह	सावन सिंह
6-	जयवंत सिंह	जयवंत सिंह
7-	कनवीर सिंह	कनवीर सिंह
8-	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
9-	हेमन्ती देवी	हेमन्ती देवी
10-	द्विपक मेठी	द्विपक सिंह
11-	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
12-	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
13-	राज प्रसाद	राज प्रसाद
14-	मनोज सिंह	M.S. Chachy
15-	अनील सिंह	अनील सिंह



(इन्द्र मोहन राणा)
ग्रामाध्यक्ष विकास अधिकारी
वि० ख० दुगड़डा
पौड़ी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड सा० नि वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)

₹0/-



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि०मी०) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम सभा का नाम- ~~पुलिण्डा~~ ग्राम -पुलिण्डा
तहसील-कोटद्वार जिला- पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

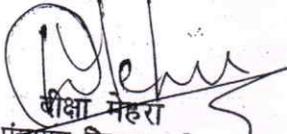
उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० -1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.080 हे० सिविल वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि 0.7875 हे०) 1.8675 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम सभा - ~~पुलिण्डा~~ के ग्राम - पुलिण्डा द्वारा दिनांक 12-08-2012 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

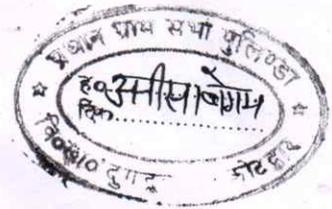
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम- पुलिण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग दुगड़डा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित


वीक्षा मेहरा
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.....
विकास खण्ड-दुगड़डा

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



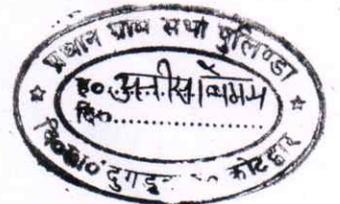
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि वि०

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0
-1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड़डा ब्लाक के
पुलिण्डा -तच्छाली - स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि०मी०)
ग्राम -पुलिण्डा दिनांक 12-08-2022

क्रम	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जयप्रताप सिंह	
2-	वीरेंद्र सिंह	
3	मान सिंह	
4-	चन्द्रमोहन सिंह	
5.	विमल सिंह	
6-	दलवीर सिंह	
7.	जितेंद्र सिंह	
8.	पंकज सिंह	
9.	योगेश्वर सिंह	
10	प्रशवन्त सिंह	
11	सीता देवी	
12.	जगदीश	
13.	नवीन सिंह	
14	रूपजीत सिंह	

ह०/-
ग्राम प्रधान

वीरेंद्र सिंह
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र.....
विकास खण्ड-दुगड़डा



काफ़ी ज़रूरी सटपापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
दुगड़डा (गढ़वाल)